



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 322]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 7, 2015/अग्रहायण 16, 1937

No. 322]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 7, 2015/AGRAHAYANA 16, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2015

विषय : इरान, कतर और चीन जनवादी गणराज्य के मूल अथवा वहां से निर्यातित 'लाइनीयर अल्काइल बेंनजीन' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

सं. 14/20/2015-डीजीएडी.—अतः मै. तमिलनाडु पेट्रो-प्रोडक्ट्स लि. और मै. नीरमा लि. (जिन्हें इसके बाद याचिकाकर्ता कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इससे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसे बाद में प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें इरान, कतर, सउदी अरब और चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ' लाइनीयर अल्काइन बेंनजीन' (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने और उन पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

2. और अतः प्राधिकारी प्रथमदृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए इरान, कतर और चीन जनवादी गणराज्य (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध

के पर्याप्त साक्ष्य हैं और प्राधिकारी एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी। प्राधिकारी ने जांच की अवधि का सउदी अरब से संबद्ध वस्तुओं के निर्यातों पर नकारात्मक क्षति मार्जिन पाया। इसलिए सउदी अरब को वर्तमान जांच के एक संबद्ध देश के रूप में नहीं माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

3. विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादक की ओर से मै. तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लि. और मै. नीरमा लि. द्वारा यह याचिका दायर की गई है। आवेदकों ने जांच की अवधि में संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। संबद्ध वस्तुओं के दो अन्य घरेलू उत्पादक हैं, नामतः मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. और मै. इंडियन आयल कारपोरेशन लि. जिन्होंने आवेदन का समर्थन किया है। संबद्ध वस्तुओं के कुल घरेलू उत्पादन में आवेदक के उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। अतः आवेदक नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है और संबंधित नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार पात्रता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद इरान, कतर और चीन जनवादी गणराज्य के मूल की अथवा वहां से निर्यातित 'लाइनर अल्काइल बेंनजीन' है।

5. विचाराधीन उत्पाद में मिश्रित अल्काइल बेंनजीन शामिल है। मिश्रित अल्काइल नाफ्थालेंस शामिल नहीं होती है। वाणिज्यिक बाजार भाषा-शैली में विचाराधीन उत्पाद को सामान्य तौर पर 'लाइनर अल्काइल बेंनजीन' (संक्षेप में 'एलएबी') के रूप में जाना जाता है।

6. वाणिज्यिक दृष्टि से उपलब्ध एल.ए.बी कार्बन एटमों की एक एकल शृंखल से सबद्ध एक बेंनजीन रिंग के बने तत्वों का मिश्रण होता है। चूंकि टर्मिनल कार्बन को छोड़कर अल्काइल चेन (शृंखला) के सभी कार्बनों पर बेंनजीन रिंग का अवस्थित किया जा सकता है, इसलिए विभिन्न समावयव (आइसोमर) संभव होते हैं। किसी भी दिए गए उत्पाद के लिए प्रति अल्काइल शृंखलाओं के कार्बनों की संख्या दस से सोलह के बीच होती है।

7. विचाराधीन उत्पाद सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची-1 के उप शीर्षक सं. 38170011 के अंतर्गत आता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल निर्देशात्मक है और यह किसी भी प्रकार से उत्पाद कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

8. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि भारत में पाटित की जा रही संबद्ध वस्तुएं घरेलू उद्योग द्वारा उत्पन्न वस्तु के समान हैं। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं, आयातित उत्पाद में वास्तविक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए इन्हें नियमों के अंतर्गत 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए।

संबद्ध देश

9. वर्तमान जांच में संबद्ध देश ईरान, कतर और चीन जनवादी गणराज्य हैं।

सामान्य मूल्य**चीन**

10. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मानना चाहिए और नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किए जाने चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने विधिवत समायोजित भारत में उत्पादन लागत के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का दावा किया है। नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 के अनुसार यह अनुमान लगाया जाता है कि चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में कार्य कर रहे हैं। उपर्युक्त गैर-बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी अनुमान तथा चीन जनवादी गणराज्य के प्रक्रिया दिखाने वाले निर्यातकों द्वारा इसका खण्डन करने के अध्यक्षीन चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य का नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार अनुमान लगाया गया है।

इरान और कतर

11. याचिकाकर्ताओं ने यह दावा किया है कि संबद्ध देशों के घरेलू बाजारों में जिस मूल्य पर इन वस्तुओं को बेचा जा रहा है, उस कीमत के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए प्रयास किए गए थे। तथापि, मूल्यों के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी। अतः याचिकाकर्ता ने संबद्ध देशों के विधिवत समायोजित उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन किया है।

निर्यात कीमत :

12. याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तावित जांच अवधि के दौरान निर्यात कीमतों के भारित औसत पर विचार करते हुए डीजीसीआईएंडएस के सौदे वार आयात आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, बैंक प्रभार, कमीशन, पत्तन एवं अंतर्देशीय भाड़ा व्ययों के लिए निर्यात कीमतों में फैक्ट्री से बाहर निर्यात कीमत का मूल्यांकन करने के लिए अतिरिक्त समायोजन किया गया है।

पाटन मार्जिन

13. सामान्य मूल्यों की फैक्ट्री से बाहर निर्यात कीमत से तुलना की गई है, जो पाटनरोधी जांच शुरुआत को उचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों द्वारा निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के संबंध में अत्यधिक पाटन मार्जिन को प्रदर्शित करता है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

14. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि संबद्ध देशों के विरुद्ध पाटनरोधी जांच की शुरुआत को औचित्यपूर्ण ठहराने के लिए पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से आयातों में सापेक्ष रूप से और क्षति की अवधि के दौरान भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में वृद्धि हुई है। इन आयातों से घरेलू कीमतों में अत्यधिक मूल्यह्रास हुआ है और तत्पश्चात घरेलू कीमतों का क्षरण हुआ है। इसके अलावा घरेलू उद्योग के निष्पादन पर लाभ, लगाई गई पूंजी पर आय घाटे, नकद हानियां और निवेशों पर ऋणात्मक आई हो रही है।

जांच अवधि

15. घरेलू उद्योग के लिए प्रस्तावित जांच अवधि 1 अप्रैल, 2014 से 30 मार्च, 2015 (12 महीने) तक निर्धारित की है। तथापि, प्राधिकारी ने इसे 1.4.2014 से 30.6.2015 तक 3 महीनों के लिए बढ़ा दी है ताकि हाल ही में आंकड़ों का मूल्यांकन किया जा सके। तथापि, क्षति विश्लेषण अवधि में अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012, अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013, अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 की अवधियां और जांच की अवधि शामिल है।

सूचना प्रस्तुत करना

16. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने और प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय,

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग,

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग,

नई दिल्ली-110001

17. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समयसीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

समय-सीमा

18. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी प्राप्त होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

19. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरुआत की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की आवश्यकता अथवा अन्यथा के बारे में की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

20. प्रश्नावली के उत्तरों/निवेदनों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा करने के मामले में इस दो अलग-अलग सेटों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए - (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) और (ख) अगोपनीय रूप से अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) दी गई समस्त सूचना के प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर 'गोपनीय' अथवा 'अगोपनीय' स्पष्ट रूप से अंकित कर देना चाहिए।

21. गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत की गई सूचना को प्राधिकारी के द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी किसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा गोपनीय वृत्तांतों की 2-2 प्रतियां और अगोपनीय वृत्तांतों की 5-5 प्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिए।

22. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी सूचना क्यों प्रकट नहीं की जा सकती है और/अथवा ऐसी सूचना का संक्षेपण क्यों संभव नहीं है।

23. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु के समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, विषय परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

24. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

25. सार्थक गोपनीयता रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

26. नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

27. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकता है अथवा अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए.के. भल्ला, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2015

Subject: Anti Dumping investigation concerning imports of ‘Linear Alkyl Benzene’ originating in or exported from Iran, Qatar and China PR

No. 14/20/2015-DGAD.—Whereas M/s Tamilnadu Petroproducts Ltd. and M/s. Nirma Ltd (hereinafter as "petitioners") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter as "the Authority") in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter as "the Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter as "the Rules") for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti dumping duty on the imports of ‘Linear Alkyl Benzene’ (hereinafter as "the subject goods") originating in or exported from Iran, Qatar, Saudi Arabia and China PR.

2. And whereas, the Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from Iran, Qatar and China PR (hereinafter as "the subject countries"), ‘injury’ to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and ‘injury’ exist to justify initiation of an anti-dumping investigation; the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the ‘injury’ to the domestic industry. The Authority found negative injury margin on imports of subject goods from Saudi Arabia for the period of investigation. Saudi Arabia is therefore not being considered as a subject country in the present investigation.

Domestic Industry & Standing

3. The application has been filed by M/s Tamilnadu Petroproducts Ltd. and M/s Nirma Ltd on behalf of the domestic producers of the product under consideration. The applicants have not imported the product under consideration from the subject countries in the period of investigation. There are two other domestic producers of the subject goods, namely, M/s. Reliance Industries Ltd and M/s Indian Oil Corporation Limited who have supported the application. The production of the applicant accounts for a major proportion of the total domestic production of the subject goods. The applicant companies therefore constitute "domestic industry" within the meaning of Rule 2 (b) and thus satisfy the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

Product under consideration

4. The product under consideration for the purpose of present investigation is “Linear Alkyl Benzene” originating in or exported from Iran, Qatar and China PR

5. The product under consideration includes Mixed Alkyl Benzenes. Mixed Alkyl Naphthalenes are excluded. The product under consideration is generally known as ‘Linear Alkyl Benzene’ (for short “LAB”) in commercial market parlance.

6. Commercially available LAB is a mixture of substances composed of a benzene ring attached to a single chain of carbon atoms. Various isomers are possible since the benzene ring may be positioned at all carbons of the alkyl chain except the terminal carbon. The number of carbons per alkyl chain ranges for any given product from ten to sixteen.

7. Product under consideration falls under sub-heading No. 38170011 of Schedule I of the Customs Tariff Act 1975. The customs classification is indicative only and in no way it is binding upon the product scope.

Like Article

8. The petitioners have claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences in the physical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the dumped imports and the domestically produced subject goods. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Rules.

Subject Countries

9. The subject countries in the present investigation are Iran, Qatar and China PR

Normal Value**China**

10. Petitioners have claimed that China PR should be treated as a nonmarket economy and determined normal value in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the Rules. The petitioners have claimed normal value for China PR on the basis of cost of production in India, duly adjusted. In terms of Para 8 in Annexure 1 to the Rules, it is presumed that the producers of the subject goods in China PR are operating under non market economy conditions. In view of the above non-market economy presumption and subject to rebuttal of the same by the responding exporters from china PR, normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure 1 to the Rules.

Iran and Qatar

11. Petitioners have claimed that efforts were made to get information about the price at which these items are being sold in the domestic markets of the subject countries. However, no information on the prices was available publicly. The petitioner has, therefore, constructed the normal value on the basis of the estimates of cost of production duly adjusted for the subject countries.

Export Price

12. The petitioners have determined the export price based on DGCI&S transaction wise import data, considering weighted average of the imports prices during the proposed investigation period. The export prices have been further adjusted for ocean freight, marine insurance, bank charges, commission, port and inland freight expenses to evaluate ex- factory export price.

Dumping Margin

13. The normal values have been compared with the ex- factory export price, which shows a considerable dumping margin in respect of the subject goods exported by the subject countries to justify the initiation of an anti- dumping investigation.

Injury and Causal Link

14. The petitioners have claimed that domestic industry has suffered material injury from dumped imports to justify the initiation of an anti-dumping investigation against the subject countries. The petitioners claim that the imports from the subject countries have increased in absolute terms and in relation to the production and consumption in India during the injury period. These imports are undercutting the domestic prices and thereafter have suppressed and depressed the domestic prices to a significant level. Further, the performance of the domestic industry has also deteriorated in terms of profits, return on capital employed and cash profits, and is therefore suffering financial losses, cash losses and negative return on investments.

Period of Investigation (POI)

15. Domestic Industry has proposed the period of investigation for the present investigation is from 1st April, 2014 to 30th March 2015 (12 months). However the authority has extended the same by 3 months as 01.4.2014 to 30.6.2015 so as to undertake analysis on the most recent data. The injury investigation period

will however cover the periods Apr'11-Mar'12, Apr'12-Mar'13, Apr'13-Mar'14 and the period of investigation.

Submission of information

16. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street,
New Delhi -110001.

17. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

Time limit

18. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

19. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Antidumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

Submission of Information on Non-Confidential basis

20. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

21. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non confidential version must be submitted by all the interested parties.

22. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

23. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

24. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or

the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

25. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

26. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

27. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

A. K. BHALLA, Designated Authority